डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 अप्रैल, 2022, डिस्पेच दिनांक 16 अप्रैल, 2022

| वर्ष 65 | अंक 22 | भोपाल | 16 अप्रैल, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

नागरिकों के जीवन मे खुशहाली लाकर मुझे अपना जीवन सार्थक बनाना है : श्री चौहान

मध्यप्रदेश का गेहूँ विदेशों में होगा निर्यात, किसानों को होगा लाभ

21 अप्रैल से फिर से शुरू होगी कन्या विवाह योजना, अब योजना में मिलेंगे 55 हजार रुपये

तीर्थ-दर्शन यात्रा 19 अप्रैल से होगी शुरू, 2 मई को मनेगा लाड़ली लक्ष्मी दिवस

कुपोषण मिटाने के लिए भी सभी मिलकर बने सहयोगी

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गाँव और नगर के विकास के लिये हर नागरिक को संकल्प लेना होगा। सभी को विकास में भागीदारी करनी होगी। राष्ट्रकवि दादा माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा थे, उन्होंने इस माटी की सुगंध को पूरी दुनिया में फैलाया है। उनके जन्म-दिवस को गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसा ही गौरव दिवस हर शहर एवं गाँव में मनाया जाए। गौरव दिवस की परिकल्पना है कि हम सब अपने गाँव और शहर के विकास में जुट जाएँ। यह सिर्फ सरकारी काम नहीं है। अपना सबका काम है, विकास की ओर बढ़ना है और एक नए मध्यप्रदेश को गढ़ना है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान माखननगर में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा गाँव, अपना शहर कैसे विकसित बने, इसकी कल्पना मिलकर करें। प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माखननगर में सफाई अभियान चलाया है। इसके लिए जिला प्रशासन, जन-प्रतिनिधि एवं क्षेत्र के नागरिकों को बधाई। इंदौर में जनता स्वच्छता अभियान से जुड गई, इसलिए इंदौर स्वच्छता में देश में नंबर वन बन गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम सबको मिलकर जल-संरक्षण, स्वच्छता और बिजली बचाने के अभियान में भी कार्य करना है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है। बीमारू राज्य से विकसित राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि गेहूँ खरीदी शुरू हो गई है। प्रदेश और नर्मदापुरम का गेहूँ विदेश में निर्यात होगा। गेहूँ एक्सपोर्ट होगा तो किसानों को और अधिक दाम मिलेंगे। हमारे प्रदेश के गेहूँ को गोल्डन ग्रेन, एमपी बीट के नाम से भी जाना जाता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गेहूँ की फसल कट गई है। गो-माता की रक्षा के लिए गोशाला खोलो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपस्थित नागरिकों से अपील की कि फसल कटाई के बाद नरवाई न जलाएँ क्योंकि इसके धुएँ से प्रदूषण फैलता है। नरवाई से भूसा बनाया जाए, जिससे गो-माता की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर में बहुत कार्य हुआ है। वहाँ कचरे से खाद और सीएनजी बनाई जा रही है। नर्मदापुरम में भी यह कार्य होना चाहिए। स्वच्छता से बीमारी से भी बचाव होता है। गाँव-गाँव तय करें कि स्वच्छता में आगे रहें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं, इसमें लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास होंगी। इन स्कूलों में गरीब बच्चे की पढ़ाई भी बेहतर हो सकेगी।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

दिल्ली में "मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022" प्रस्तुत करना राज्य की बड़ी उपलब्धि : मुख्यमंत्री श्री चौहान

प्रदेश की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए कहा कि नई दिल्ली में मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत करना प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। सुशासन और विकास पर ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर केंद्रीय मंत्रियों तथा देश के आर्थिक जगत के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मध्यप्रदेश की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम के गान के साथ आरंभ हुई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर गौरव दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। अपने गाँव, नगर के विकास, वहाँ के लोगों के कल्याण और स्थानीय लोगों की भागीदारी की भावना गौरव दिवस से अभिव्यक्त हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आरंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी ने अपने सर्वे में बताया है कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर 1.4% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में कम है। प्रदेश में रोजगार के अवसर निर्मित करने और युवाओं को स्व-रोजगार में सहयोग का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

बुनियादी सुविधाओं को जुटाए बिना विकास और सुशासन बेमानी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

समाज की सक्रिय सहभागिता से मध्यप्रदेश के सुशासन प्रयासों में मिली है सफलता

प्रधानमंत्री श्री मोदी भी देते हैं जन-भागीदारी पर जोर, मध्यप्रदेश निरंतर प्रयास करेगा

नई दिल्ली में लाँच हुई मध्यप्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आम जनता की सक्रिय सहभागिता से ही मध्यप्रदेश सुशासन के क्षेत्र में देश के सामने उदाहरण बनकर खड़ा हो सका है। आज से 15 वर्ष पहले मध्यप्रदेश जिन क्षेत्रों में बहुत पीछे था और बीमारू राज्य कहलाता था, उन क्षेत्रों में लगातार प्रगति के प्रयास किए गए, जिसका परिणाम यह है कि मध्यप्रदेश पहले विकासशील राज्य बना और अब विकसित प्रदेशों की पंक्ति में खड़ा है। मध्यप्रदेश में जन-भागीदारी से विकास का मॉडल लागू किया गया है। पिछले 02 साल में कोविड महामारी के नियंत्रण में इस मॉडल की उपयोगिता सिद्ध हुई। प्रधानमंत्री श्री मोदी भी विकास के लिए जन-भागीदारी पर जोर देते हैं। वे हमारे प्रेरक हैं। मध्यप्रदेश निरंतर जन-भागीदारी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने का कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज मध्यप्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 के लांचिंग समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में अनेक केन्द्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और मध्यप्रदेश कैडर के अखिल भारतीय स्तर के प्रशासनिक, पुलिस और वन सेवा के अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी रहकर सफलता प्राप्त की है। मध्यप्रदेश की उपलब्धियों में प्रधानमंत्री जी का निर्देशन महत्वपूर्ण रहा है। श्री मोदी भारत राष्ट्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मध्यप्रदेश में 03 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें विभिन्न योजनाओं में निर्मित की गई। बिजली का उत्पादन 05 हजार मेगावॉट से बढ़ाकर 21 हजार मेगावॉट तक पहुँचाया गया। कई बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश ने पंजाब और हरियाणा को गेहूँ उपार्जन में पीछे छोड़ दिया है। मध्यप्रदेश का सोने जैसे दानों वाला गेहूँ अमेरिका सहित अनेक देशों में निर्यात होता है। अब गेहूँ के निर्यात के लिए प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई गई है। मध्यप्रदेश में सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित सिंचाई रकबा 43 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केन-बेतवा योजना की मंजूरी से मध्यप्रदेश के बड़े इलाके को लाभान्वित करने की पहल की है। मध्यप्रदेश में अन्य नदी जोड़ों परियोजनाएँ भी क्रियान्वित हो रही हैं। प्रदेश की विकास दर 19.7 प्रतिशत देश में सर्वाधिक है। देश की अर्थ-व्यवस्था में मध्यप्रदेश 4.6 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में बीते दशक में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने इन्फ्रा सेक्टर में 48 हजार करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 हजार करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। जल जीवन मिशन के कार्यों में 12 हजार करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता देश के लिए उदाहरण बनी है। प्रदेश में 43 लाख लाड़ली लक्ष्मियाँ हैं। बालिका और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार कार्य हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 15 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने श्रमिकों, किसानों, महिलाओं, शिल्पियों, विद्यार्थियों और अन्य वर्गों की पंचायतें बुलाकर योजनाओं के स्वरूप के संबंध में सुझाव प्राप्त किए। जनता की भावनाओं का पूरा सम्मान किया गया। परिणामस्वरूप अनेक व्यवहारिक योजनाएँ निर्मित हुई। इनके क्रियान्वयन में अच्छी सफलता मिली है। मध्यप्रदेश पहला राज्य है जिसने पब्लिक सर्विस गारंटी कानून बनाया। समय पर सेवाएँ न देने वाले लोग दंडित किए जाते हैं। समाधान ऑनलाइन, सी.एम. हेल्पलाइन, वन-डे समाधान और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्य पद्धतियाँ आम जनता को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध करा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनावश्यक कानूनों को समाप्त किया गया है। अनेक प्रमाण-पत्र निश्चित समय में उपलब्ध हो जाते हैं। स्व-प्रमाणित दस्तावेज मान्य किए गए हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर ही नहीं अब संपूर्ण मध्यप्रदेश उदाहरण बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे प्रतिदिन पौधा लगाते हैं। पौध-रोपण से एकात्म हो गए हैं। नागरिकों से भी अपने जन्मदिन, परिजन के जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ आदि पर पौधे लगाने का आग्रह किया गया है। कुपोषण की समाप्ति के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प के अनुसार एडाप्ट एन आँगनवाड़ी अभियान चलाया जा रहा है। किसान भी आँगनवाड़ी केन्द्रों के लिए सहयोग देते हैं। पानी और बिजली बचाने का काम किया जा रहा है। मेरा गाँव, मेरा तीर्थ की भावना को विस्तार दिया गया है। ग्रामों और नगरों के गौरव दिवस मनाए जा रहे हैं। इस क्रम में आज नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में प्रख्यात कवि और स्वतंत्रता सेनानी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के गृह नगर में गौरव दिवस मनाया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सीएम राइज विद्यालय, श्रमोदय विद्यालय और चिकित्सा सेवाओं के विस्तार का कार्य भी किया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों और अन्य विषय-विशेषज्ञों से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय समितियों और युवाओं की समितियों के माध्यम से विकास के प्रयासों में सहयोग मिलेगा। मध्यप्रदेश ने आपदा को अवसर में बदलने के प्रधानमंत्री श्री मोदी के आव्हान के पश्चात आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संकल्प में अधोसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, रोजगार और अर्थ-व्यवस्था को प्राथमिकता दी। व्यवस्थित प्रयासों से मध्यप्रदेश सुशासन के क्षेत्र में मॉडल बनने में सफल हुआ है। प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुशासन के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के जिस काम को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमारे जिम्मे सौंपा था, उसे सबसे पहले मध्यप्रदेश ने कर दिखाया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमारू राज्य से मध्यप्रदेश को एक रोल मॉडल राज्य बना दिया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

सदस्य मानव संसाधन संवर्धन आयोग भारत सरकार डॉ. आर. बाला सुब्रमण्यम ने कहा कि मध्यप्रदेश ने सुशासन के क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य किया है। मध्यप्रदेश में जन-भागीदारी मॉडल बनाकर सबसे बढ़िया उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें प्रगति के लिए क्षमता विकास पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अपनी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दें। मध्य प्रदेश अपनी योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक के विकास के कार्य कर रहा है। मध्यप्रदेश विकास के कई पेरामीटर पर देश में आगे है।

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ शोधकर्ताओं के लिए सीएम फेलोशिप स्थापित की गई है। एमपीसीडीआर रिपोर्ट में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया गया है। विशेषकर कोविड काल में मध्यप्रदेश के जन-भागीदारी मॉडल को सराहा गया है। मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा जिसमें स्टेटिस्टिक्स कमीशन को स्थापित किया जा रहा है जो जिला स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद को मापने का कार्य करेगा। पिछले तीन क्वार्टर में लगातार मध्यप्रदेश का आंकड़ा बाकी अन्य राज्यों से काफी आगे रहा है। प्रदेश 14 राज्यों में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है।

यू.एम.ई.पी. के पूर्व कार्यकारी निदेशक श्री एरिक सोल्हेम ने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्रीन एनर्जी पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। यहाँ बड़े सोलर प्लांट लगाये गए हैं जो ग्रीन एनर्जी-क्लीन एनर्जी की ओर बहुत अच्छे कदम हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं रोज़ाना एक पौधा लगाया जाता है यह बहुत अच्छी पहल है। मध्यप्रदेश का शहर इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, इसके लिए मध्यप्रदेश को बधाई।

संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक श्री शोम्बी शार्प ने अपने संबोधन में कहा कि मध्यप्रदेश ने हर समुदाय तक पहुँच सुनिश्चित की है और यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी पीछे न छूटे। यह इसके टीकाकरण अभियान में सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया था, जिसमें सामुदायिक भागीदारी ने अहम भूमिका निभाई। देश के कई अन्य राज्य और दुनिया के कई अन्य देश प्रगति और विकास के मामले में मध्य प्रदेश के अनुभवों से सीख सकते हैं। श्री शार्प ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र समावेशी और सतत विकास की दिशा में मध्य प्रदेश के साथ अपने एसडीजी सहयोग को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केन्द्रीय सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत श्री बी श्रीनिवास ने कहा कि मध्यप्रदेश में सुशासन की समृद्ध परंपरा रही है। चाहे लोक सेवा गारंटी कानून हो, सी.एम. हेल्पलाइन, जन-सुनवाई या फिर एफआईआर आपके द्वार, मध्यप्रदेश सुशासन का पथप्रदर्शक रहा है। इंदौर के स्वच्छता जन-भागीदारी मॉडल और अनूपपुर के स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम की प्रशंसा सभी करते हैं।

सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ग्राम सभाओं को बनाना होगा सशक्त : मंत्री श्री सिसोदिया

सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय हितधारक का हुआ सम्मेलन

भोपाल : पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति और ग्रामीण विकास के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। सभी विभागों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से ही यह संभव हो पाएगा। मंत्री श्री सिसोदिया आज विज्ञान भवन में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री सिसोदिया ने बताया कि गुना जिले की ग्रामीण शालाओं में विद्यार्थियों के उपयोग के लिए मनरेगा से मध्यान्ह भोजन के लिए सीमेंट की बेंच और टेबल उपलब्ध कराई गई है, जिससे ग्रामीण विद्यार्थियों में आत्म-विश्वास पैदा हुआ है। श्री सिसोदिया ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह से इस क्रांतिकारी योजना को पूरे देश में लागू करने का आग्रह किया। श्री सिसोदिया ने सुझाव दिया कि आर्थिक उद्धार के लिए आजीविका के क्षेत्र में स्व-सहायता समूहों को मार्केटिंग एप्स से जोड़कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायता से देश-विदेश में ग्रामीण और जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है।

मंत्री श्री सिसोदिया ने मनरेगा योजना से फर्जी जॉब कार्ड की समस्या को दूर करने के लिए सुझाव दिया कि स्थानीय स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निगरानी की जाए, जिससे योजना में पारदर्शिता आएगी। श्री सिसोदिया ने कहा कि सरिया की बढ़ती कीमतों को देखते हुए पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में मिलने वाली राशि को बढ़ाया जाए अथवा छत की डिजाइन में बदलाव किया जाए, जिससे ग्रामीण हितग्राहियों का लाभ हो सके। श्री सिसोदिया ने आवास पोर्टल को पुनः चालू करने का भी आग्रह किया।

उल्लेखनीय है कि आजादी का अमृत महोत्सव में पंचायती राज मंत्रालय के "पंचायतों के नवनिर्माण का संकल्पोत्सव" विषय पर आईकॉनिक सप्ताह समारोह का उद्घाटन आज नई दिल्ली में उप राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह, केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल सहित राज्यों के पंचायती राज मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

केंद्रीय संचार मंत्रालय के प्रशासक एवं नीति आयोग के प्रभारी अधिकारी ने ग्रामों का दौरा किया

विदिशा : केंद्रीय संचार मंत्रालय के प्रशासक एवं नीति आयोग द्वारा विदिशा जिले के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी (आईएएस) श्री हरिरंजन राव ने सोमवार को विदिशा विकासखण्ड के ग्रामों का भ्रमण कर नीति आयोग के मापदंड अनुसार क्रियान्वित कार्यों का धरातलीय जायजा ही नही लिया बल्कि योजनाओं व कार्यक्रमों से लाभांवित होने वालो से संवाद किया है।

नीति आयोग के प्रभारी अधिकारी आईएएस श्री हरिरंजन राव विदिशा विकासखण्ड के ग्राम हांसुआ स्थित आरसेटी प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर स्व सहायता समूह के सदस्यों से संवाद स्थापित कर प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर प्रशिक्षण क्यों प्राप्त कर रहे हो जिस विधा में प्रशिक्षण ले रहे हो ग्रामीण क्षेत्र में उसका स्कोप क्या है इत्यादि की जानकारी ही नहीं प्राप्त की बल्कि प्रशिक्षणार्थियों की मूलभूत जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।

प्रभारी अधिकारी श्री राव ने ग्राम भाटनी में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचकर आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं का अवलोकन किया साथ ही विभिन्न संधारित पंजियों में दर्ज करने की प्रक्रिया तथा ऑन लाइन अपलोड करने की जानकारियों की मौके पर क्रास मानिटरिंग की है। आंगनबाडी केन्द्र में भण्डारित पोषण आहार टेक होम राशन (टीएचआर) के पैकेटों का अवलोकन कर उनकी एक्सपायरी डेट की जानकारी प्राप्त की है।

उन्होंने आंगनबाड़ी में भर्ती बच्चों से संवाद किया उन्होंने यहां मौजूद आंगनबाड़ी कर्मियों से भी चर्चा की उन्होंने आंगनबाड़ी में उपस्थित सीएचओ से स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी लेने के उपरांत स्वयं का ब्लड प्रेशर की जांच कराई है।

उन्होंने ग्राम के सरपंच से कहा कि ग्राम में नियुक्त हुई सीएचओ की जानकारी पूरे ग्रामीण में प्रसारित कराई जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आती है तो प्रारंभिक उपचार के रूप में परीक्षण कराकर आवश्यक दवाईयां त्वरित प्राप्त कर सकें। उन्होंने सीएचओ से कहा कि गर्भवती महिलाओं से सतत सम्पर्क बनाए रखें ताकि डिलेवरी के दौरान किसी भी प्रकार की क्रिटिकल स्थिति निर्मित ना हो सकें।

केंद्रीय संचार मंत्रालय के प्रशासक एवं नीति आयोग के प्रभारी अधिकारी आईएएस श्री हरिरंजन राव आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लेने के उपरांत ग्राम भाटनी में ही मौजूद रोजगार सहायक के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यो से अवगत ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने स्वयं कम्प्यूटर आपरेट किया और ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा बहाली के संबंध में जानकारी प्राप्त की है।

उन्नत कृषि के लिये नवाचारों को अपनायें किसान - कृषि मंत्री श्री पटेल

इंदौर में फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले और प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों से उन्नत कृषि के लिये नवाचारों को अपनाने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा है कि पारम्परिक कृषि के स्थान पर उन्नत कृषि करना जरूरी है। सरकार किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है, ताकि उनकी आय को दोगुना किया जा सके। मंत्री श्री पटेल इंदौर में फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले और प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। कृषि सम्मेलन में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि 4 दिवसीय कृषि मेले और प्रदर्शनी में किसानों को नवीन तकनीकी और नवाचारों एवं उपयोग और प्रयोग से निश्चित ही किसानों को लाभ होगा। उनकी आय में वृद्धि होगी, जो आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक होगी। श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं किसान पुत्र हैं। उनके नेतृत्व में किसानों को लाभान्वित करने के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व और प्रदेश के किसानों के परिश्रम से ही हम लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। मंत्री श्री पटेल ने मेले में शामिल हुए किसानों से कहा कि अधिक से अधिक किसानों को कृषि मेले में आने से उन्हें नवीन जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी।

प्रदर्शनी में कृषि और बागवानी, मशीनरी, ग्रीनहाउस और पॉलीहाउस प्रौद्योगिकी, ट्रैक्टर निर्माता, टायर निर्माता, पाइप्स और पम्प्स निर्माता, सिंचाई और जल संचयन, डेयरी मशीनरी, पशु आहार, खाद, बीज कीटनाशकों के उत्पादकों द्वारा नवीन एवं अद्यतन तकनीकों के बारे में जानकारी दी जायेगी। प्रदर्शनी में पोंड लाइनर, ट्रेक्टर, मल्चिंग, कृषि एवं बागवानी,यन्त्र, बीज, खाद्य एवं जैविक खाद्य, ड्रोन टेक्नोलॉजी के जीवंत प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।

सम्मेलन में कृषि प्र-संस्करण, डेयरी प्र-संस्करण, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने और जैविक खेती पर तकनीकी सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, ताकि किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिल सके। प्रदर्शनी में 200 से अधिक स्टॉल लगाये गये हैं, जिसमें कृषि की

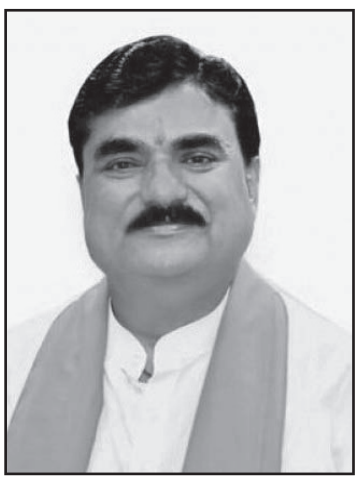

अद्यतन तकनीकों का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन में इटली, जर्मनी और यूएसए की कंपनियां भी अपनी अद्यतन तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने सभी किसानों से अपील की है कि कृषि मेले और प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिये आयें, नवीन तकनीकों से अवगत हों और अधिक से अधिक लाभ कमाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के सपने को साकार करें।

रोजगार, राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री चौहान

तीन माह में 13 लाख 63 हजार युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा

प्रदेश में निवेश लाकर रोजगार के अवसर किए जा रहे सृजित

प्रदेश में 650 से अधिक नई इकाइयों में होगा 40 हजार करोड़ से अधिक का निवेश

अपना मध्यप्रदेश बढ़ता मध्यप्रदेश है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की इंदौर के स्टार्ट-अप की प्रशंसा

युवा व्यवसाय में नवाचार करें, राज्य सरकार उनके साथ है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ

भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में युवाओं को विनिर्माण, व्यवसाय और सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख से 50 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण लेने वाले युवाओं को 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। योजना में युवाओं को बैंक गारंटी नहीं देनी होगी, सरकार युवाओं की ओर से गारंटी लेगी। इसके लिए 140 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार बैंकों में जमा करेगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक है, उन परिवारों के युवा इस योजना में ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना प्रदेश के युवाओं के लिए नई आशा और उम्मीद का संदेश लेकर आई है। आज 2019 युवाओं को लगभग 108 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए गए। राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। रोजगार उपलब्ध कराना हमारे लिए एक यज्ञ के समान है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के शुभारंभ अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने की। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री राम खिलावन पटेल, आयुष राज्य मंत्री श्री राम किशोर कांवरे, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ. पी. एस. भदौरिया तथा रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर युवा के चेहरे पर मुस्कान हो, वह आत्म-विश्वास से परिपूर्ण हो। युवा आत्म-निर्भर बनें, राज्य सरकार रोजगार दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रदेश में एक क्रांति का आरंभ है। आजीविका, व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता है, इसलिए राज्य सरकार रोजगार और स्व-रोजगार के लिए समग्र रूप से प्रयासरत है। शासकीय सेवा में भर्ती के लिए भी अभियान चलाया गया है। स्कूल शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की गई है। साथ ही पुलिस आरक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि यह वास्तविकता है कि सभी युवा सरकारी नौकरी से रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। अत: स्व-रोजगार की व्यवस्था करना आवश्यक है। प्रदेश में निवेश लाकर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रति माह एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाने के क्रम में पहले रोजगार दिवस 12 जनवरी को 5 लाख 25 हजार से अधिक हितग्राहियों को स्व-रोजगार के लिए 2700 करोड़ रूपए, दूसरे रोजगार दिवस 25 फरवरी को 5 लाख 2 हजार से अधिक हितग्राहियों को स्व-रोजगार के लिए 2,776 करोड़ रूपए और तीसरे रोजगार दिवस 30 मार्च को 3 लाख 33 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2,268 करोड़ रूपए से अधिक की ऋण सहायता स्वीकृत की गई। इस प्रकार गत तीन महीनों में 13 लाख 63 हजार युवाओं को विभिन्न योजनाओं में स्व-रोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरा सपना है कि प्रदेश के बेटा-बेटी, रोजगार माँगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश में 650 से अधिक नई इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। इनमें 40 हजार करोड़ रूपए से अधिक का निवेश होना है। इससे रोजगार के एक लाख नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की विकास दर इस वर्ष 19.7 प्रतिशत है, जो देश में सबसे अधिक है। प्रदेश की जीडीपी बढ़ कर साढ़े ग्यारह लाख करोड़ हो गई है। प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश ने इस वर्ष 40 हजार करोड़ रूपए का निर्यात किया है। प्रदेश में हो रहे गेहूँ और चावल का उपयोग दुनिया के देश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अपना मध्यप्रदेश बढ़ता मध्यप्रदेश है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मनुष्य केवल साढ़े तीन हाथ का हाड़--मांस का पुतला नहीं हैबल्कि ईश्वर का अंश और अनंत शक्ति का भंडार है। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं, जो वह नहीं कर सकता। जो लोग अपनी सोच को क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं वे सफल होते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर के विभिन्न सफल स्टार्ट-अप का उल्लेख करते हुए कहा कि नए परिवेश और बदलती तकनीक के अनुरूप व्यवसाय में नए विचारों का बहुत महत्व है। युवा व्यवसाय क्षेत्र में नवाचार करें, राज्य सरकार उनके साथ है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत
मिडिल एवं प्रायमरी स्कूल के बच्चों को खड़ी मूंग का वितरण

विदिशा : मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण तहत जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के छात्र-छात्राओं को साबुत मूंग का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के संचालक द्वारा समय सीमा में कार्यो के संपादन हेतु दायित्व सौंपे गए है।

जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने बताया कि जिले के शासकीय मिडिल एवं प्रायमरी स्कूलों में अध्ययनरत रहें विद्यार्थी जिन्हें नवम्बर 2020 से अगस्त 2021 तक अवधि अर्थात 176 दिवसों के लिए खड़ी मूंग का वितरण किया जाना है इसके लिए जिले के एक लाख 39 हजार का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। बच्चों को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्रदाय की जाएगी। संबंधित शैक्षणिक संस्था के गुरूजन पूर्व उल्लेखित स्कूलों के बच्चों को अपने साथ लाएंगे और उचित मूल्य दुकानों से निर्धारित मात्रा मिडिल क्लास के हरेक बच्चे के लिए 15 किलो ग्राम तथा प्रायमरी स्कूलों के प्रत्येक बच्चें को दस किलोग्राम खडी मूंग दाल निर्धारित थैलों में भरी हुई प्रदाय की जाएगी।

उक्त वितरण कार्यक्रम के पूर्व खड़ी मूंगदाल एवं थैले सभी उचित मूल्य दुकानों पर 09 अप्रैल 2022 पूर्व पहुंचाना सुनिश्चित करने निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रेषित किए गए है। इस संबंध में मुख्य सचिव के निर्देशानुसार निर्धारित दायित्वों का समयावधि में आवंटित कार्य पूर्ण करने हेतु कहा गया है।

जिपं पंचायत सीईओ डॉ भरसट ने बताया कि खड़ी मूंग वितरण कार्य हेतु जिन विभागों को आवश्यक जबावदेंही सौंपी गई है वे समय सीमा में उसका क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। जारी पत्र अनुसार विपणन संघ के लिए जो जबाबदेंही सौंपी गई है उनमें तीन अप्रैल तक आवंटन अनुसार प्रदाय केन्द्रों को खड़ी मूंग का परिवहन करना एवं पांच अप्रैल तक योजना अनुसार प्रदाय केन्द्र स्थल पर थैलो का प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। इसके अलावा जिले के एमपीएससीएससी के प्रबंधकों एवं सहायक आपूर्ति के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है तदानुसार नौ अप्रैल तक प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य दुकानों को मूंग का प्रदाय करना एवं प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य दुकानों के संचालकों को बुलाकर थैले प्रदाय करने का कार्य किया जाएगा। जबकि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पांच अप्रैल तक जिले के लाभार्थी छात्र-छात्राओं को आधार, समग्र आईडी से लिंक नहीं किया जा सका है तो उनको उचित मूल्य दुकान से मूंग की प्राप्ति हेतु पर्ची का प्रारूप एवं ऐसे लाभार्थियों को मूंग के वितरण हेतु नोडल अधिकारी का नामांकन कार्य संपादित किया जाएगा। वहीं खाद्य विभाग, एसडीएम व एनआईसी के द्वारा तीन अप्रैल तक पोर्टल पर लाभार्थी विद्यार्थियों के आधार कार्ड, समग्र आईडी लिंक करने के कार्य पूरे किए जाएं ताकि विद्यार्थियों को साबुत मूंग का प्रदाय कार्य सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न हो सकें। आयोजन पूर्व जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक में संबंधितों को दिशा निर्देश दिए गए है।

प्रदेश में 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना

32 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश की संभावना

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के संशोधन को मंजूरी दी। योजना में सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित पात्र प्रति कन्या के मान से 55 हजार रूपये स्वीकृत किये जायेंगे। इस राशि में से 6 हजार रूपये की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी एवं रूपये 38 हजार रूपये की सामग्री एवं 11 हजार रूपये का एकाउण्ट पेयी चेक कन्या को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा प्रदाय किये जायेंगे।

श्रम विभाग के मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिक हेतु विवाह सहायता योजना को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में समाहित किया जायेगा।

कार्यक्रम के लिए अधिकृत संस्था सामूहिक विवाह का आयोजन शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत ही आयोजनकर्ता होंगे। अन्य किसी संस्था द्वारा कराये जा रहे सामूहिक विवाह इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होंगे।

जिला एवं निकाय स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह आयोजन समिति

सामूहिक कन्या विवाह/निकाह कार्यक्रम का सुचारू रूप से आयोजन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला एवं निकाय स्तरीय समितियों का गठन जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जायेगा। इन समितियों में वरिष्ठ शासकीय अधिकारी भी सदस्य होंगे।

जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा जिले के प्रत्येक निकाय के लिए सामूहिक विवाह एवं निकाह हेतु 2-2 तिथियों का वित्तीय वर्षवार कैलेण्डर जारी होगा। इस कैलेण्डर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे इच्छुक जोड़ों द्वारा समय पर आवेदन किया जा सकें।

कन्या को 49 हजार रूपये की राशि गृहस्थी की स्थापना हेतु आवश्यक उपहार सामग्री प्रदाय की जायेगी। जिला एवं निकाय स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह आयोजन समिति प्रदाय की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

आवेदन की प्रक्रिया पूर्वानुसार रहेगी, जिसके अनुसार वर-वधु को सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम के आयोजन की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त आवेदन करना होगा।

विवाह हेतु हितग्राहियों की पात्रता की जाँच सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिवस पूर्व पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होगी। सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम का सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। योजना की शेष शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेगी। योजना में किये गये सभी संशोधनों को समाहित कर नवीन दिशा-निर्देश एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे।

32 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश की संभावना

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 05 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों को 714.56 करोड़ रूपये की लागत से विकसित किये जाने का प्रशासकीय अनुमोदन दिया। बैरसिया जिला भोपाल परियोजना लागत 25.88 करोड़, आष्टा (झिलेला) जिला सीहोर 99.43 करोड़, धार (तिलगारा) जिला धार 79.43 करोड़ मेगा औदयोगिक पार्क रतलाम फेस-1 जिला रतलाम 462 करोड़ और नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर 47.82 करोड़ की परियोजना शामिल है। इन 5 नवीन औदयोगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में लगभग 32 हजार करोड़ रूपये से अधिक का निवेश होना संभावित है। साथ ही 38 हजार 450 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

ग्रामीण बैंकों के लिए पुनर्पूजीकरण सहायता योजना

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकरण सहायता योजना में कुल राशि 1414.83 करोड़ रूपये की अंशपूँजी सहायता स्वीकृत की, जिसमें राज्य शासन के हिस्से की राशि 212.23 करोड़ रूपये है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूँजी में राज्यांश हिस्से की राशि के निवेश के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूँजी में भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार राज्य शासन के हिस्से की राशि 212.23 करोड़ रूपये का निवेश किया जाये।

प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 1320 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं, जिनमें से 1172 शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र में है। इन बैंकों द्वारा मुख्यतः ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ वित्तीय समावेशन से प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं। वर्तमान में इन बैंकों का प्रदेश में कुल व्यवसाय 40 हजार करोड़ रूपये से अधिक का है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पुनर्पूंजीकरण सहायता से इन बैंकों द्वारा अपने व्यवसाय में वृद्धि की जा सकेगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण किये जाने से रोजगार के नये अवसर निर्मित हो रहे हैं। इस पुनर्पूंजीकरण सहायता से इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिये और अधिक वित्त पोषण किया जा सकेगा।

पशुपालन गतिविधियों को बढ़ाने शून्य प्रतिशत ब्याज दर

मंत्रि-परिषद ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग में प्रदेश में पशुपालन गतिविधियों हेतु किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से गाय, भैंस, बकरी, सूकर, मुर्गी पालन हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अधिकतम राशि 2 लाख रूपये की साख सीमा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। पशुपालन गतिविधियों हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करने की योजना के क्रियान्वयन से राज्य में पशुपालक आसानी से आदान खरीद सकेंगे तथा सूदखोरों और बिचौलियों से बचाव होकर पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।

सिंचाई परियोजनाएँ

मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले की कयामपुर दाबयुक्त सूक्ष्म उद्वहन वृहद सिंचाई परियोजना लागत राशि 2374 करोड़ रूपये, सिंचाई क्षमता एक लाख 12 हजार हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना के निर्माण से सीतामऊ एवं मंदसौर तहसील के 252 ग्रामों की एक लाख 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन से सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) सुविधा प्राप्त होगी।

मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले की ताखाजी सूक्ष्म मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 46.86 करोड़ रूपये, सिंचाई क्षमता 3200 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना के निर्माण से भानपुर तहसील के 9 ग्रामों की 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) की सुविधा प्राप्त होगी।

मंत्रि-परिषद ने लामटा पाइप इरीगेशन नेटवर्क (होज सिस्टम) परियोजना लागत राशि 146.50 करोड़ रूपये, सिंचाई क्षमता 9630 हेक्टर खरीफ सिंचाई हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से बालाघाट जिले की लामटा तहसील के जनजातीय बहुल 55 ग्रामों को भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई (होज) पद्धति से खरीफ सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा।

फायर सर्विसेज योजना की निरंतरता

मंत्रि-परिषद ने आग की रोकथाम के लिए संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अधीन प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए प्रचलित फायर सर्विसेज योजना को निरन्तर रखते हुए अग्नि सुरक्षा उपायों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदेश की नगरीय निकायों में नवीन फायर स्टेशन निर्माण, प्रशिक्षण भवन, हाइड्रोलिक प्लेटफार्म/टीटीएल, एडवांस रेस्क्यू टेण्डर, वाटर टेण्डर, क्विक रिस्पॉस वीहिकल, इन्फ्लेटेबल लाइटनिंग टॉवर, फायर फाइटिंग बाईक, फायर सूट, वाटर ब्राउजर, रेस्क्यू बोट, जीपीएस सिस्टम आदि कार्यों के लिये भारत सरकार को 241 करोड़ रूपये से अधिक की प्रेषित कार्य-योजना की 10 प्रतिशत राज्यांश राशि 24.19 करोड़ रूपये एवं कुल 282 नगरीय निकायों को 10 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण करने वाली 326 फायर वाहनों के स्थान पर नवीन फायर वाहन क्रय करने राज्यांश की 75 प्रतिशत राशि 18.75 लाख रूपये के मान से राशि 61.13 करोड़ रूपये, इस प्रकार कुल राशि 85.32 करोड़ रूपये की कार्य-योजना की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।

पुनर्घनत्वीकरण नीति-2022

मंत्रि-परिषद ने शहरी क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवन/परिसरों के लिए पुनर्घनत्वीकरण नीति- 2016 के स्थान पर पुनर्घनत्वीकरण नीति: 2022 को लागू किये जाने का अनुमोदन किया।

राज्य स्तरीय सशक्त समिति के गठन का निर्णय

वर्तमान नवीन तकनीकी युग में नित नई तकनीकों, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं का आविष्कार जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में हो रहे हैं। वर्तमान में ऐसे अनेक विषय है, जिनसे नवीन सामग्री, प्रक्रिया एवं उत्पाद प्रौद्योगिकी तथा नवीन नवाचार समाधान को शासन के कार्य क्षेत्रों में अपनाये जाने से उत्पादकता, उपयोगिता एवं गुणवत्ता में सुधार के साथ प्रदेश में नवीनतम तकनीकों को अंगीकृत किया जा सकेगा। ऐसे विषयों पर विचार-मंथन कर शासकीय विभागों के लिये अपनाये जाने के संबंध में परीक्षण करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः "नवीनतम तकनीक में नवाचार और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) के गठन का निर्णय लिया गया। यह समिति समग्र विचारोपरान्त नवीन तकनीक अथवा प्रस्ताव को प्रयोगात्मक या पायलट के रूप में क्रियान्वित करने की अनुशंसा करेगी।

विवाद से विश्वास योजना की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ी

ग्वालियर : मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिना सम्मति प्राप्त संचालित उद्योगों और संस्थानों के लिये लागू 'विवाद से विश्वास' योजना की अवधि 30 अप्रैल, 2022 तक बढ़ा दी है। पूर्व में यह अवधि एक जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक थी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उद्योग, जिनके द्वारा कभी भी सम्मति नहीं ली गई है, उनको प्रथमत: स्थापना सम्मति प्राप्त करनी होगी। साथ ही जिन उद्योगों ने स्थापना और उत्पादन की सम्मति ली है, लेकिन उसका नवीनीकरण नहीं कराया है, वे भी उक्त योजना अवधि में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में सम्मति आवेदन करने वाले उद्योगों पर पूर्व वर्षों की अवधि के लिये देय स्थापना/उत्पादन सम्मति की शुल्क दरें वर्तमान विनिधान राशि पर देय होंगी। विलंब शुल्क देय नहीं होगा।

प्रदेश के सभी जिलों में लगेंगे महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर : मुख्यमंत्री

व्याधियों की जाँच कर दिलवाया जाएगा उपचार

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी जिलों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच और परीक्षण के बाद आवश्यक उपचार की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रदेश की स्त्री रोग विशेषज्ञों और चिकित्सकों के साथ सभी चिकित्सकों को अपने दायित्व निर्वहन के लिए सुरक्षित वातावरण और परिवेश उपलब्ध है। यह आदर्श स्थिति बनी रहे, इस दिशा में भी संबंधित एजेंसियों को सक्रिय रखा जाएगा। इंदौर में हो रहे पाँच दिवसीय स्त्री रोग विशेषज्ञ अधिवेशन में प्रस्तुत शोध-पत्रों के निष्कर्षों के अनुसार राज्य सरकार जरूरी प्रबंध भी करेगी।

मध्यप्रदेश में बढ़ा संस्थागत प्रसव का आँकड़ा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह अधिवेशन इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि गत दो वर्ष में कोरोना की वजह से गतिविधियाँ स्थगित थी। इस अधिवेशन की रूपरेखा के लिए फॉग्सी संस्था बधाई की पात्र है। मध्यप्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य हुआ है। उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाया गया है। लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाएँ बहुत सफल रही हैं। प्रदेश में लिंगानुपात प्रति एक हजार बेटों पर 912 बेटियों के जन्म से आगे बढ़कर 956 तक पहुँच गया है। हमारा प्रयास और लक्ष्य यह है कि यह संख्या समान हो जाए। बेटे और बेटियों में कोई भेद न हो।

ग्रामीण महिलाओं के उपचार में विशेषज्ञों के अनुभव होंगे उपयोगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राय: संकोच के कारण बहुत सी महिलाएँ अपनी शारीरिक तकलीफ को व्यक्त नहीं करती, जिसके कारण उनकी तकलीफ ब्रेस्ट और यूट्रस कैंसर में बदल जाती है। विलंब होने से समुचित उपचार भी संभव नहीं हो पाता। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आशा व्यक्त की कि यह अधिवेशन स्त्री रोग विशेषज्ञों के तकनीकी कौशल, श्रेष्ठ नवाचारों और अनुभवों के परस्पर आदान-प्रदान के बाद महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने लाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उम्मीद व्यक्त की कि प्रसूति और स्त्री रोगों की चुनौतियों को नित्य प्रति अनुभव करने वाले विशेषज्ञ सरकार को भी आवश्यक दिशा दिखाने का कार्य करेंगे। ग्रामीण महिलाओं के बेहतर उपचार के लिए अनुभवी चिकित्सक और विशेषज्ञों के चिकित्सा सेवा से संबंधित अनुभवों के आदान-प्रदान और निष्कर्ष उपयोगी सिद्ध होंगे। मध्यप्रदेश में शिशु और मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आयी है, इसे और भी कम करने के प्रयासों को तेज किया जाएगा। वर्तमान में संस्थागत प्रसव 92 प्रतिशत हो रहे हैं, जो शत-प्रतिशत होने लगे, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं के अन्य रोगों के निराकरण के लिए भी व्यवस्थाओं को सशक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबल योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के पोषण और आहार के लिए राशि के प्रावधान, ऐसे परिवारों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा और कॅरियर निर्माण के लिए सहयोग देने का भी उल्लेख किया।

(पृष्ठ 1 का शेष)

नागरिकों के जीवन मे खुशहाली लाकर....

उन्होंने कहा कि हम मध्यप्रदेश में नया इतिहास रच रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई अब हिन्दी में होगी। अपने देश में अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी सीखना बुरा नहीं है। निज भाषा की उन्नति होना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 21 अप्रैल से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर से शुरू हो रही है। योजना में राशि 51 हजार से बढ़ाकर अब 55 हजार रूपये कर दी गई है। इसमें गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए समिति बनाई जाएगी। जिला स्तरीय समिति तय करेगी कि अच्छा सामान बेटी को मिले। उन्होंने कहा कि 2 मई को लाड़ली लक्ष्मी दिवस मनेगा। साथ ही तीर्थ-दर्शन यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। गरीब और मेधावी बच्चों की मेडिकल कॉलेज की फीस सरकार देगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कुपोषण दूर करना है। आँगनवाड़ी में गरीब बच्चे आते हैं, उन्हें वहाँ अच्छा खाना मिलेगा तो वे कुपोषित नहीं होंगे। किसान भाई आँगनवाड़ी के लिये अनाज दे सकते हैं। गाँव का मेरा बच्चा दुबला, पतला नहीं होना चाहिए।

सब मिलकर करें बिजली पानी की बचत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बिजली और पानी की बचत को हमें अपनी आदत में शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 21 हजार करोड़ रूपये बिजली के लिए दिए हैं, तब गरीब तबके को सस्ती बिजली मिलती है। हम संकल्प लें कि व्यर्थ बिजली नहीं जलाएंगे। फिजूल खर्ची बंद कर दें तो 4 हजार करोड़ बचा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष पानी के लिए नल-जल योजना पर 12 हजार करोड़ खर्च किये जा रहे हैं। इसके लिए भी संकल्प लें कि फालतू पानी नहीं बहाएंगे। पानी जितना बचा सकें बचाएँ, पानी बचेगा तो दूसरों के काम आएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार जनता के लिए काम करती है। इस काम में जनता को भी सहयोग करना चाहिए। क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए आमजन भी उसकी निगरानी करें। उन्होंने कहा कि अपराधियों और गुंडे-बदमाश की अवैध जमीन पर बुलडोजर चल रहा है। अन्याय करने वालों को ऐसा तोडूंगा कि जीने के लायक नहीं रहेंगे। अन्याय समाप्त करना है। अपराधियों का दमन करना जरूरी है। सभी संकल्प ले कि रिश्वत नहीं देंगे। बुराइयों की समाप्ति के लिए कदम उठाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा नाश की जड़ है। नर्मदा किनारे शराब की दुकान नहीं खुलेंगी। प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाना है। सभी संकल्प लें कि अपने गाँव को नशा मुक्त करेंगे। धीरे-धीरे नशा की बुराई को नष्ट करें। हम चाहते हैं कि प्रदेश में राम राज्य आए।

एक सौ करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने माखननगर के गौरव दिवस पर 100 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पं. माखनलाल चतुर्वेदी की स्मृति में माखननगर में ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा भी की।

नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास कर रहा है। पिछले दिनों होशंगाबाद जिले का नामकरण नर्मदापुरम किया गया और आज पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के जन्म-दिवस पर उनके जन्म स्थान बाबई का नामकरण "माखननगर" किया गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों में खुशी का माहौल है।

सांसद श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रतिदिन दौरे करते हैं और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जायजा लेते हैं। साथ ही प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं। उनके प्रयासों से ही हमारा प्रदेश बीमारु प्रदेश की श्रेणी से निकलकर विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आ गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया है।

विधायक सोहागपुर श्री विजय पाल सिंह ने बाबई का नामकरण माखन नगर किए जाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट किया। उन्होंने क्षेत्र के वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने तथा पेयजल समस्या वाले कुछ ग्रामों में नदी पर स्टॉप डेम बनाने का अनुरोध मुख्यमंत्री श्री चौहान से किया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान से अनुरोध किया कि माखननगर में दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की स्मृति में सांस्कृतिक भवन बनाया जाए। कार्यक्रम में छात्राओं ने मनमोहक जनजातीय लोक नृत्य प्रस्तुत किया।

गेहू फसल का उजार्जन सप्ताह में 5 दिवस

अशोक नगर : रबी विपणन वर्ष 2022-23 हेतु जिला अशोकनगर कृषकों की फसल का उपार्जन 57 सेवा सह समितियों/स्व-सहायता समूहो द्वारा 16 मई तक किया जाएगा। कृषकों की उपज का क्रय सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक किया जाएगा एवं कृषक तौल पर्ची 6:00 बजे तक जारी की जाएंगी। प्रत्येक पंजीकृत कृषक द्वारा अपनी उपज का विक्रय करने हेतु ऑनलाईन http://mpeuparjan.nic.in/पर स्वयं के मोबाईल/एमपी ऑनलाईन /सीएससी/ ग्राम पंचायत / लोक सेवा केन्द्र/इन्टरनेट कैफे उपार्जन केंद्र से स्लॉट बुकिंग करने का प्रावधान किया गया है। कृषक द्वारा स्वयं के मोबाइल, ग्राम पंचायत, उपार्जन केंद्र से निशुल्क स्लॉट बुकिंग की जा सकती है। कृषकएमपी ऑनलाईन /सीएससी/ ग्राम पंचायत / लोक सेवा केन्द्र/इन्टरनेट कैफे प्रति स्लॉट बुकिंग शुल्क10 रूपए निर्धारित किया गया है। इसकी सूचना संबंधित संस्थाओं पर लगाई जाना आवश्यक है। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि किसी भी स्थिति में कृषक से प्राप्त नहीं की जा सकेगी। प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर गेहूं सफाई के लिए गेहूं सफाई मशीन ,छलनी की व्यवस्था उपार्जन केंद्र द्वारा की जाएगी। इस कार्य के लिए दर प्रति क्विंटल 20 रूपए से अधिक नहीं होगी। सेवा प्रदाता कृषक से गेहूं सफाई हेतु प्रति क्विंटल 20 रूपए सीधा प्राप्त करेगा। अधिक राशि किसी भी स्थिति में वसूल नहीं की जा सकेगी। इसकी सूचना प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करना अनिवार्य है ।

(पृष्ठ 1 का शेष)

दिल्ली में मध्यप्रदेश सुशासन ....

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले 3 माह में 14 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध कराकर स्व-रोजगार से लगाया गया है। यह समन्वित प्रयास का परिणाम है। उद्यम क्रांति योजना प्रदेश के युवाओं के लिए वरदान सिद्ध होगी।

योजना का प्रस्तुतिकरण

मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले उद्यम क्रांति योजना पर प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसमें योजना के उद्देश्य, पात्रता, पात्र परियोजना, बैंकों की भूमिका, वित्तीय सहायता के प्रकार, आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया आदि की जानकारी दी गई। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल से होगा और बैंक द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह में आवेदन पर निर्णय लिया जाना अनिवार्य किया गया है।

अप्रैल महीने में शुरु करें इन फसलों की बुवाई

अप्रैल एक ऐसा महीना होता है जब रबी की फसलें कट चुकी होती हैं और किसान इन फसलों को मण्डी में बेचकर खेती से राहत में होता है। इसके बाद किसान अगली जायद की फसलों की तैयारी कर रहे होते हैं। अप्रैल में गेहूं की कटाई और जून में धान/मक्का की बुवाई के बीच लगभग 50 से 60 दिन खेत खाली रहते हैं। इस समय किसान इन खाली खेतों में बागवानी, सब्जियों की खेती एवं कई नगदी फसलों की खेती कर धान/मक्का की बुवाई से पहले 50 से 60 दिनों में नगदी कमा सकते हैं। इस समय किसान अपने कुछ कमजोर खेतों में हरी खाद बनाने के लिए ढैंचा, लोबिया या मूंग इत्यादि फसलों की खेती कर सकते हैं। इस प्रकार की खेती से किसानों को अधिक लाभ के साथ-साथ उर्वरक खर्च से निजात मिलता है। क्योंकि इन फसलों से उपज प्राप्त होने के बाद किसान जून में बोई जाने वाली फसल धान रोपने से एक-दो दिन पहले या मक्का बोने से 10-15 दिन पहले मिट्टी में जुताई करके इन्हें मिट्टी में मिलाने पर मिट्टी की सेहत सुधरती है। और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है।

इस महीने कराएं अपने खेतों की मिट्टी की जांच

जैसा कि हम सभी जानते हैं रबी सीजन की फसलों की कटाई के बाद अप्रैल महीने में किसानों के खेत खाली हो जाते हैं। ऐसे में किसान अपने खाली खेत की मिट्टी की जांच करा सकते हैं। किसान हर तीन वर्षों में एक बार अपने खेतों की मिट्टी परीक्षण जरूर कराएं ताकि मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों (नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, लोहा, तांबा, मैंगनीज व अन्य) की मात्रा और फसलों में कौनसी खाद कब व कितनी मात्रा में डालनी है, का पता चले। मिट्टी जांच से मिट्टी में खराबी का भी पता चलता है ताकि उन्हें सुधारा जा सके। जैसे कि क्षारीयता को जिप्सम से, लवणीयता को जल निकास से तथा अम्लीयता को चूने से सुधारा जा सकता है। साथ ही किसान इस महीने में अपने खेतों में हरी खाद के लिए जायद की फसलों में जैसे उड़द, मूंग, सोयाबीन, सेम, ढैंचा इत्यादि हरी खाद फसलों की बुवाई अवश्य करें। अप्रैल में अपने खेत के आसपास के क्षेत्रों में स्थित टयूबवैल व नहर के पानी की भी जांच करायें। ये जांच आप हर मौसम में करवा लें ताकि पानी की गुणवत्ता के हिसाब से आप इस महीनें फसल का चयन कर सकें।

इस महीने करें इन फसलों की बुवाई

उड़द

उड़द की खेती के लिए नम और गर्म जलवायु की आवयकता होती हैं। वृद्धि के समय 25-35 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान उपयुक्त होता है। हालांकि यह 43 डिग्री सेंटीग्रेट तक का तापमान आसानी से सहन कर सकती है। 700-900 मिमी वर्षा वाले क्षेत्रों में उड़द को आसानी से उगाया जाता है। अधिक जल भराव वाले स्थानों पर इसकी खेती उचित नहीं है। बसन्त ऋतु की फसल फरवरी-मार्च में तथा खरीफ ऋतु की फसल जून के अन्तिम सप्ताह या जुलाई के अन्तिम सप्ताह तक बुवाई कर देते है। उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की भूमि मे होती है। हल्की रेतीली, दोमट या मध्यम प्रकार की भूमि जिसमे पानी का निकास अच्छा हो उड़द के लिये अधिक उपयुक्त होती है। पी.एच. मान 7-8 के बीच वाली भूमि उड़द के लिये उपजाऊ होती है। उड़द का बीज 6-8 किलो प्रति एकड़ की दर से बोना चाहिये। बुबाई के पूर्व बीज को 3 ग्राम थायरम या 2.5 ग्राम डायथेन एम-45 प्रति किलो बीज के मान से उपचारित करे। जैविक बीजोपचार के लिये ट्राइकोडर्मा फफूँद नाशक 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपयोग किया जाता है।

सोयाबीन

अगर किसान इस महीने में सोयाबीन बोएं, तो इसमें बीमारियां लगने की मात्रा कम होती है और फसल भी बारिश शुरू होने से पहले ही अच्छे से तैयार हो जाती है। सोयाबीन दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो जिनमे वायुमंडलीय नत्रजन संस्थापित करने की क्षमता होती हैं जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। सोयाबीन की सबसे बेस्ट वैरायटी -आरकेएस 24 (RKS 24) Soybean Variety है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्कीत रेतीली व हल्की भूमि को छोड्कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है परन्तु पानी के निकास वाली चिकनी दोमट भूमि सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्ती होती है। जहां भी खेत में पानी रूकता हो वहां सोयाबीन ना लें। ग्रीष्मे कालीन जुताई 3 वर्ष में कम से कम एक बार अवश्यि करनी चाहिए।

ढ़ैंचा

ढैंचा एक कम अवधि (45 दिन) की हरी खाद की फसल है। गर्मियों के दिनों में 5 से 6 सिंचाई करके ढैंचा की फसल को तैयार कर लेते हैं तथा इसके बाद धान की फसल की रोपाई की जा सकती है। ढैंचा की फसल से प्रति हेक्टेयर भूमि में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन इकट्ठी हो जाती है। जुलाई या अगस्त में ढैंचा की फसल की बुआई कर, 45 - 50 दिन बाद खेत में दबाकर, हरी खाद का काम इस फसल से ले सकते हैं। भूमि का पी.एच. मान 9.5 होने पर भी इसे उगा सकते हैं। अतः लवणीय व क्षारीय भूमियों के सुधार के लिए यह सर्वोत्तम है। भूमि का पी.एच. मान 10 - 5 तक होने पर लीचिंग अपनाकर या जिप्सम का प्रयोग करके इस फसल को उगा सकते हैं। इस फसल से 45 दिन की अवधि में लवणीय भूमियों में

200 - 250 क्विंटल जैविक पदार्थ भूमि में मिलाया जा सकता है।

अरहर

सिंचित अवस्था में टी-21 और यू.पी.ए.एस. 120 किस्में अप्रैल में लग सकती है। इसकी खेती के लिए हल्की दोमट अथवा मध्यम भारी प्रचुर स्फुर वाली भूमि, जिसमें समुचित पानी निकासी हो, अरहर बोने के लिये उपयुक्त है। खेत को 2 या 3 बाद हल या बखर चलाकर तैयार करना चाहिये। खेत खरपतवार से मुक्त हो तथा उसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था की जावे। अरहर की फसल के लिए समुचित जल निकासी वाली मध्य से भारी काली भूमि जिसका पी.एच. मान 7.0-8.5 का हो उत्तम है। अरहर के सात किग्रा. बीज को राइजोबियम जैव खाद के साथ उपचारित करके एक फुट दूर लाईनों में बोए। अरहर की दो लाइनों के बीच एक मिश्रित फसल (मूंग या उड़द) की लाइन भी लगा सकते हैं, जोकि 60 से 90 दिन तक काट ली जाती है। अरहर की खेती करने से 15-20 क्विंटल/हेक्टेयर उपज असिंचित अवस्था में और 25-30 क्विंटल/हेक्टेयर उपज सिंचित अवस्था में प्राप्त कर सकते है।

इस महीने करें इन नगदी सब्जियों की खेती

मार्च से अप्रैल माह के मौसम को कई मुख्य सब्जी लगाने के लिए यह समय उपयुक्त माना जाता है। बाजार में अच्छे दाम मिल सके, इसलिए मार्च अप्रैल में कई सब्जियों की बुवाई की जाती है। इस महीने में बुवाई की जाने वाली मुख्य शाकभाजी लौकी, भिंडी, करेला, तोरई, बैंगन आदि है।

भिंडी

यह फसल ग्रीष्म तथा खरीफ, दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। भिंडी को उत्तम जल निकास वाली सभी तरह की भूमियों में उगाया जा सकता है। भूमि का पी0 एच मान 7.0 से 7.8 होना उपयुक्त रहता है। भिंडी की फसल में बीजो को अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। इसके बाद जब पौधें अंकुरित हो जाते है तब इन पौधो को विकसित होने के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। भिंडी की पंजाब-7 किस्म भिंडी की यह किस्म पीतरोग रोधी होती है, इस किस्म के पौधें 50 से 55 दिन के अंतराल में तोड़ने के लिए तैयार हो जाते है। यह देखने में हरे तथा सामान्य आकर के होते है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर 8 से 20 टन की पैदावार करती है।

लौकी

लौकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से इसकी खेती के लिए मार्च से अप्रैल महीने उपयुक्त माना जाता है। इसकी बुआई गर्मी एवं वर्षा के समय में की जाती है। यह पाले को सहन करने में बिलकुल असमर्थ होती है। इसलिए लौकी की खेती में 30 डिग्री के आसपास का तापमान इसके लिए काफी अच्छा होता है। बीजो के अंकुरित होने के लिए सामान्य तथा पौधों को वृद्धि करने के लिए 35 से 40 डिग्री तक के तापमान की आवश्यकता होती है इसकी खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती हैं किन्तु उचित जल धारण क्षमता वाली जीवांश्म युक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गयी हैं। लौकी की खेती में भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। काशी गंगा: लौकी की इस किस्म को अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। यह लगभग 400 से 450 क्विंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार देती है। इसमें हरे तथा सामान्य आकार के फल होते है, यह लम्बाई में एक से डेढ़ फीट तक लम्बे होते है। लौकी की यह किस्म बीज रोपाई के 50 से 55 दिन बाद फल देना आरम्भ कर देते है।

करेला

भारत में अधिकांश किसान करेले की फसल का उत्पादन 1 वर्ष में दो बार करते है। सर्दियों के समय में बोये जाने वाले करेले की किस्मों को जनवरी-फरवरी में बुआई कर मई-जून में इसका उत्पादन प्राप्त कर लेते है। जबकि गर्मियों के समय में करेले की किस्मों की बुआई जून और जुलाई में करने के पश्चात इसकी उपज दिसंबर तक मिल जाती है। करेले की फसल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। यदि हम तापमान की बात करे, तो फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेट और अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच होना चाहिए। करेले की बढ़वार के लिए न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 35 -40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। खेत में बनाये हुए हर थाल में चारों तरफ 4-5 करेले के बीज 2-3 सेमी गहराई पर बो देना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु की फसल हेतु बीज को बोआई से पूर्व 12-18 घंटे तक पानी में रखते हैं। पौलिथिन बैग में एक बीज प्रति बैग ही बोते है। पंजाब करेला-1: इस किस्म को अधिक पैदावार के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह किस्म करेले की 1 एकड़ में किसान को लगभग 50 से 60 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाता है।

बैंगन

बैंगन (सोलेनम मैलोंजेना) सोलेनैसी जाति की फसल है, जो कि मूल रूप में भारत की फसल मानी जाती है और यह फसल एशियाई देशों में सब्जी के तौर पर उगाई जाती है। बैंगन की अच्छी उपज के लिये गहरी दोमट भूमि, जिसमें जीवांश की पर्याप्त मात्रा हो एवं उचित जल निकासी वाली भूमि को सबसे अच्छी समझी जाती है। इसकी फसल के लिए भूमि का पीएच मान 5 से 7 के मध्य होना चाहिए। इसके पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। एक हेक्टेयर खेत में बैगन की रोपाई के लिए समान्य किस्मों का 250-300 ग्रा. एवं संकर किस्मों का 200-250 ग्रा, बीज पर्याप्त होता है। पूसा हाइब्रिड-6: इस किस्म के पौधा लगाने का समय- गर्मी के दिनों के लिये उपयुक्त है। पौधा लगाने के 60-65 दिनों के बाद पहली तुड़ाई की जा सकती है। फल का ओसत वजन 200-250 ग्राम तक हो सकता है। इस किस्म की बुवाई करके प्रति हेक्टेयर 40-60 टन पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

तोरई

किसान ग्रीष्मकालीन तोरई की बुवाई मार्च-अप्रैल माह में कर सकते हैं, साथ ही इसकी वर्षाकालीन फसल को जून से जुलाई में बो सकते हैं। तोरई की अच्छी फसल के लिए कार्बनिक पदार्थो से युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में उचित जल निकासी वाली भूमि की जरूरत होती है। सामान्य पीएच मान वाली भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधे अच्छे से वृद्धि करते है। तोरई के पौधे सामान्य तापमान में अच्छे से अंकुरित होते है। इसके पौधे अधिकतम 35 से 40 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते है। किसान ध्यान दें कि तोरई की बुवाई के लिए लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 3-5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। तोरई की बुवाई के लिए नाली विधि ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। पूसा चिकनी (घिया तोरई) किस्म को अधिक उगाया जाता है, इसके पौधों में निकलने वाले फल चिकने, मुलायम तथा गहरे हरे रंग के होते है। यह अधिक पैदावार देने वाली किस्म है जो बोने के 45 दिनों में बाद पैदावार देने लगती है। इस किस्म की पैदावार इसकी अच्छी फसल की देखभाल पर निर्भर होती है। तोरई की इस किस्म से लगभग 200-400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल सकती है।

समर्थन मूल्य की खरीदी व आर्बीटिशन प्रकरण तैयार करने हेतु प्रशिक्षण आयोजित

भोपाल। पैक्स प्रबंधकों हेतु लीकेज (हानि) की रोकथाम एवं समर्थन मूल्य की खरीदी व आर्बीटेशन प्रकरण तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण दिनांक 28, 29, 31 मार्च 2022, एवं 04,05,06,07,08,11 अप्रैल 2022 को एक–एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिसमे 287 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में पैक्स प्रबंधकों को पैक्स में लिकेज(हानि) के कारण एवं नियंत्रण के उपाय, पैक्स पर कर दायित्व, जीएसटी एवं आयकर का रिटर्नस तथा पैनाल्टी, समर्थन मूल्य खरीदी में क्षति की पूर्ति हेतु आर्बीट्रेशन के तहत दावा प्रस्तुत करना एवं प्रबंधक की भूमिका, आर्बीट्रेशन की प्रकिया, दावा प्रस्तुति हेतु वैधानिक कार्यवाही, समर्थन मूल्य खरीदी, बिल प्रस्तुत करना, क्लेम पत्रक तैयार करना एवं आडिट कराना आदि की प्रक्रिया एवं प्रबंधक की भूमिका विषयों पर विषय विशेषज्ञों – श्री श्रीकुमार जोशी से.नि. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, श्री प्रदीप नीखरा, से.नि. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, श्री पी.के.एस. परिहार, से.नि. वरि.प्रबंधक, अपेक्स बैंक, श्री अंशुल अग्रवाल एवं श्री योगेश जैन चार्टर्ड एकाउंटेंट, श्री डी.के. सक्सेना व श्री अनूप शर्मा वरि. अधिवक्ता, श्री अविनाश सिंह व श्री संजय सिंह, वरि.सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

गबन धोखाधडी एवं अंकेक्षण, विभागीय कार्य निष्पादन विषय पर प्रशिक्षण आयोजित

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारी आंदोलन को सशक्त एवं प्रभावी बनाने हेतु सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षकों के लिए प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन के मार्गदर्शन में प्रभावी प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है –

दिनांक 4 से 6 अप्रैल एवं 11 से 13 अप्रैल 2022 तक दो सत्र में सहकारी निरीक्षकों हेतु गबन धोखाधडी एवं अंकेक्षण, विभागीय कार्य निष्पादन विषय पर प्रशिक्षण दिया गया जिसमें – भारतीय दंण्ड संहिता के तहत गबन, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की व्याख्या एवं प्रावधान, वर्तमान में प्रदेश में प्राप्त महत्वपूर्ण गबन अपराधियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं अपराध पूर्व रोकथाम, भारतीय दण्ड संहिता के तहत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं दस्तावेज (सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में), गबन, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत आदि प्रकरणों का न्यायालयीन निर्णय हेतु प्रमुख तथ्य समस्या एवं समाधान, संस्थाओं के वित्तीय पत्रको का परीक्षण तकनीकी पैरामीटर के आधार पर–सी.आर., ए.आर, एन.पी.ए एवं अन्य पैरामीटर पर कर प्रतिवेदन दर्ज करना, सहकारी संस्थाओं में गबन एवं धोखाधड़ी के मुख्य प्रकार एवं उनके तथ्यों का प्रकटीकरण (साख संरचना कें परिप्रेक्ष्य में), संस्थाओं के अंकेक्षण में सी.बी.एस. एवं डी.एम. आर. एकाउन्ट का परीक्षण करना एवं वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त करना, संस्थाओं के वित्तीय पत्रको के परीक्षण–निरीक्षण एवं टैक्स लायबलिटी (जी.एस.टी., इंकम टैक्स आदि) का परीक्षण एवं अंकेक्षण टीप में शामिल किया जाना, सहकारी संस्थाओं को हुई हानि की पूर्ति हेतु की जाने वाली विधिक कार्यवाही एवं अन्य पृथक वैधानिक प्रतिवेदन, वर्तमान में संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु जारी अद्यतन परिपत्र एवं उनका पालन कर वित्तीय अनियमितताओं पर रोकथाम, प्रशासक, निर्वाचन अधिकारी, परिसमापक, अंकेक्षक, कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य निष्पादन, कर्तव्य पालन, उत्तरदायित्व, संवेगात्मक बुद्वि, वर्क लाइफ बैलेंस (समय, एवं तनाव प्रबंधन), पर आयोजित किया गया। जिसमें प्रदेश के 40 प्रतिभागी उपस्थित रहे, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी माहों में भी निरन्तर आयोजित किये जाते रहेंगे।

आजीविका मिशन के कर्मचारियों को सहकारी समितियों का ऑनलाइन पंजीयन पर प्रशिक्षण सम्पन्न

भोपाल। आयुक्त सहकारिता श्री संजय गुप्ता व प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा आजीविका मिशन के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु एक दिवसीय सहकारी समितियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण दि. 11.04.2022 को सम्पन्न हुआ। जिसमें कुल 56 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ द्वारा ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया के वैद्यानिक प्रावधान, ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया एवं कठिनाईयों का निराकरण पर श्री प्रवीण डबगर, आई. प्रभारी, सहकारी संस्थाओं को समयबद्ध वैद्यानिक रिपोर्ट/प्रपत्र तैयार करना एवं पंजीयन सहकारिता को प्रेषित करना पर श्री श्रीकुमार जोशी, से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता, पंजीकृत सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन पर श्री प्रदीप नीखरा, से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित

(म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

Higher Diploma in Cooperative Management (HDCM)

माध्यम - ऑनलाईन

योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण अवधि - 20 सप्ताह ऑनलाईन आवेदन/ प्रवेश की अंतिम तिथि – 31 मई 2022

कुल फीस - 20200/-

ऑनलाइन आवेदन / प्रवेश हेतु राज्य संघ के पोर्टल www.mpscuonline.in पर विजिट करें।

संपर्क :-

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित , भोपाल

ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159

मो. 8770988938 , 9826876158

Website-www.mpscu.in, Web Portal-www.mpscuonline.in

Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006

फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053

Email - ctcindore@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

हनुमान ताल जबलपुर, म.प्र पिन - 482001

फोन- 0761-2341338 मो. 9424782856 , 8827712378

Email - ctcjabalpur@gmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव

जिला छत्तरपुर, म.प्र. पिन – 471201

फोन- 07685-256344 मो. 9630661773

Email - ctcnowgong@gmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।